



 सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

 www.prharyana.gov.in | Follow us on        @diprharyana



सुशासन ही आधार
डबल इंजन हरियाणा सरकार

संदेश

प्याए प्रदेशवासियो,

कोई भी व्यवस्था समकालीन जरूरतों और लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर बनाई जाती है। समय बदलने से जरूरतों और लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। यदि नए वक्त के अनुसार व्यवस्था में बदलाव न किया जाए तो उसकी हालत ठहरे हुए पानी जैसी हो जाती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रचनाकारों ने हर 5 साल बाद चुनाव का प्रावधान किया ताकि कुछ नए लोगों को अवसर मिले और वे नए वक्त व जरूरतों के अनुरूप बदलाव कर सकें।

इसी तरह के बदलाव की उम्मीद के साथ वर्ष 2014 में हरियाणा की जनता ने हमें जनसेवा का दायित्व सौंपा था। व्यवस्था में बदलाव का यह काम जटिल होता है, लेकिन नीयत साफ हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। बदलाव के इस दौर से गुजरते हुए आज जब हम व्यवस्था की धारा को सबसे पहले-सबसे गरीब की तरफ मोड़ने में सफल हुए हैं, तो सुशासन के संकल्प से शुरू हुई हमारी यात्रा सबके लिए, समय पर, सरलता से, सही सेवा सुनिश्चित करने की मंजिल पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

इस मंजिल को पाने के लिए हमें कई पड़ावों से गुजरना पड़ा है। पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार के बल पर अनेक ऐसी अच्छी चीजें हुई हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं। हम बड़े-बड़े भवन, पुल,

सड़कें आदि बनाने तक ही विकास को सीमित नहीं मानते, इसलिए समय पर सर्विस डिलीवरी, समानता, समरसता व अंत्योदय पर विशेष बल दिया है।

इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिया गया 'सबका साथ-सबका विकास - सबका विश्वास' का मूलमंत्र



हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ की तरह मार्गदर्शक रहा है। हरियाणा एक - हरियाणवी एक, समान व समावेशी विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के हमारे लक्ष्य इसी मूलमंत्र से निकले हैं।

पिछले 8 साल का दौर केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने तक सीमित नहीं है। हम प्रदेश के हैप्पीनेस इन्डैक्स को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईज़ ऑफ लिविंग की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हमने सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क, स्वावलम्बन आदि सुनिश्चित करने के लिए नई-नई पहल की हैं। हमने सबके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। स्वामित्व योजना में सम्पत्ति का स्वामी बनाया है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान की है। पुराने विवादों को निपटाकर आगे बढ़ने के लिए उनका समाधान किया है। इन सब प्रयासों व पहलों और इनके परिणामों का विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है।

आने वाला हरियाणा 21वीं सदी का विकसित प्रदेश होगा, जहां शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियां और मजबूत होंगी। हम 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका सम्मान' की आदर्श नीति पर चलते हुए कार्य करते रहेंगे, जिससे चुस्त, जिम्मेदार, भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था दृढ़ता से कायम रहे।

जयहिन्द! जय हरियाणा!

मुख्यमंत्री, हरियाणा

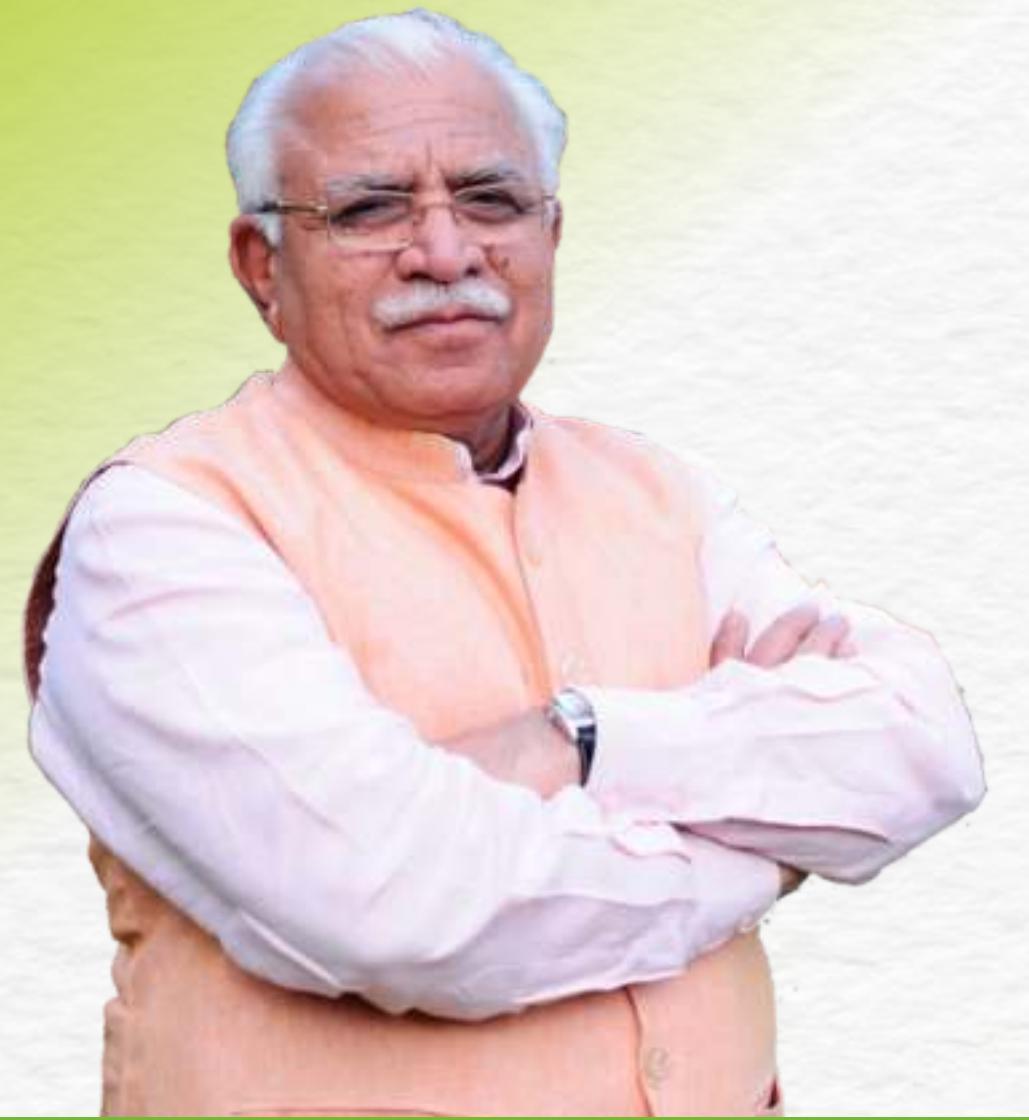
कोई भी व्यवस्था समकालीन जरूरतों और लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर बनाई जाती है। समय बदलने से जरूरतों और लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। यदि नए वक्त के अनुसार व्यवस्था में बदलाव न किया जाए तो उसकी हालत ठहरे हुए पानी जैसी हो जाती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रचनाकारों ने हर 5 साल बाद चुनाव का प्रावधान किया ताकि कुछ नए लोगों को अवसर मिले और वे नए वक्त व जरूरतों के अनुरूप बदलाव कर सकें।

इसी तरह के बदलाव की उम्मीद के साथ वर्ष 2014 में हरियाणा की जनता ने हमें जनसेवा का दायित्व सौंपा था। व्यवस्था में बदलाव का यह काम जटिल होता है, लेकिन नीयत साफ हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। बदलाव के इस दौर से गुजरते हुए आज जब हम व्यवस्था की धारा को सबसे पहले-सबसे गरीब की तरफ मोड़ने में सफल हुए हैं, तो सुशासन के संकल्प से शुरू हुई हमारी यात्रा सबके लिए, समय पर, सरलता से, सही सेवा सुनिश्चित करने की मंजिल पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

इस मंजिल को पाने के लिए हमें कई पड़ावों से गुजरना पड़ा है। पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार के बल पर अनेक ऐसी अच्छी चीजें हुई हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं। हम बड़े-बड़े भवन, पुल,

सड़कें आदि बनाने तक ही विकास को सीमित नहीं मानते, इसलिए समय पर सर्विस डिलीवरी, समानता, समरसता व अंत्योदय पर विशेष बल दिया है।

इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिया गया 'सबका साथ-सबका विकास - सबका विश्वास' का मूलमंत्र



श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

कैबिनेट मंत्री



श्री दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री



श्री अनिल विज
गृह मंत्री



श्री कंवर पाल
शिक्षा मंत्री



श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री



श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री



श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री



डॉ. बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री



डॉ. कमल गुप्ता
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री



श्री देवेन्द्र सिंह बदली
विकास एवं पंचायत मंत्री

राज्य मंत्री



श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार



श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार



श्री अनूप धानक
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार



श्री संदीप सिंह
खेल एवं युवा मामले,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

अनुक्रमणिका

1. हमारा लक्ष्य-अंतिम का उदय
2. सुशासन से उद्धार-सेवा घर द्वार
3. सबका साथ-सबका विकास
(हरियाणा एक-हरियाणवी एक)
4. कृषि एवं किसान कल्याण
5. स्वास्थ्य
6. युवा-कल्याण
7. शिक्षा
8. खेल एवं तंदुरुस्ती
9. सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण
10. सुरक्षा
11. वन एवं पर्यावरण संरक्षण

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

39

12. संस्कृति एवं पुरातत्व

13. कर्मचारियों को सुविधाएं

14. महिला एवं बाल कल्याण

15. उद्योग

16. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

17. स्वावलंबन-शहरी स्थानीय निकाय

18. ग्राम विकास

19. श्रमिक कल्याण

20. हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों/आपातकालीन पीड़ितों को सुविधाएं

21. हरियाणा को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

43

47

51

55

59

65

69

73

77

79



हमारा लक्ष्य
अंतिम का उदय



फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्तूबर-2014	अब
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1000 रुपये मासिक	2500 रुपये मासिक
विवाह शागुन राशि	31,000 रुपये	71,000 रुपये
अनुसूचित जाति को कानूनी वित्तीय सहायता	5500 रुपये	22,000 रुपये
बी.पी.एल., अनुसूचित जाति को मकान मरम्मत के लिए	25,000 रुपये	80,000 रुपये
ग्रामीण सफाईकर्मियों का वेतन	8100 रुपये मासिक	14,000 रुपये मासिक
बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा	1.20 लाख रुपये	1.80 लाख रुपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी	21.82 लाख	30.78 लाख
अन्तर्राजीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि	50 हजार रुपये	2.50 लाख रुपये





हमारा लक्ष्य-अंतिम का उदय बातें नहीं-बदलाव

- ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के तहत सबसे गरीब 33 हजार लोगों को रोजगार के लिए ऋण।
- ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत 9 लाख बी.पी.एल. परिवारों को 276 करोड़ रुपये की मदद।
- पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (ए) को 8 प्रतिशत आरक्षण।
- ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ – 27 लाख परिवारों को अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक मुफ्त राशन।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण।
- गरीब परिवारों के छात्रों की 12वीं कक्षा तक व छात्राओं की स्नातकोत्तर कक्षा तक फीस माफ।
- अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग।
- अनुसूचित जातियों के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी।
- अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित औद्योगिक प्लाट पर 10 प्रतिशत की छूट।
- ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ – 34,000 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण।
- ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना’ में अनुसूचित जाति के परिवार को तीन बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपये।
- ‘अंत्योदय आहार योजना’ – 10 जिलों में 10 रुपये में भोजन।
- ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ – गरीब परिवारों को 9.20 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन।
- ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ – 10 लाख अंत्योदय परिवार कवर तथा 17 लाख अन्य परिवारों को जल्द लाभ।
- ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ – 32 हजार लोगों को अपना घर मिला, 24 हजार मकान निर्माणाधीन।
- ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ – 86.70 लाख बैंक खाते खोले गए।
- ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ – 53.17 लाख लोग शामिल।
- ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ – 19.80 लाख लोगों को लाभ।
- ‘अटल पेंशन योजना’ – 8.33 लाख लोगों का पंजीकरण।
- ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ – 21.45 लाख लोगों को 21,455 करोड़ रुपये का ऋण।
- ‘स्वच्छ भारत मिशन’ – 7.41 लाख व्यक्तिगत शौचालयों व 5910 सामुयायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।
- ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)’ – 1.14 लाख ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्शन।

मुख्य बातें

परिवार पहचान—पत्र योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे

डी.बी.टी.—142 योजनाओं के 56,257 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में

1 लाख युवाओं को योग्यता आधार पर सरकारी नौकरी

अंत्योदय सरल पोर्टल से 49 विभागों की 649 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन ठेका प्रथा बंद

हरियाणा कौशल रोजगार निगम—आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद



सुशासन से उद्धार सेवा घर द्वारा



4. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी – 43 विभागों के 214 कॉडर में लागू।
5. एकल पंजीकरण—नौकरी के लिए बार-बार आवेदन व फीस से छुटकारा।
6. हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा—112 पर 9,20,563 कॉल्स का समाधान।
7. जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी रोकने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के बेबाकी प्रमाण-पत्र (NDC) ऑनलाइन।
8. ई-भूमि वैब पोर्टल – जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक।
9. ई-ऑफिस – सरकारी कामकाज में तेजी।
10. माल ढुलाई में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ऑप्रेशन शुद्धि।
11. खनन ठेकों में ई-नीलामी और ई-रवाना स्कीम से पारदर्शिता।
12. 40 नए कानून बनाए तथा पुराने 32 नियमों और कानूनों में समय की जरूरत के अनुसार संशोधन।



सुशासन से उद्धार-सेवा घर द्वारा बातें नहीं-बदलाव

1. सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह भावना पैदा हुई है कि सरकार उनकी है और वे सरकार में हैं।
2. सी.एम. विंडो – 9.37 लाख शिकायतों का समाधान।
3. ऑटो अपील सॉफ्टवेयर – 31 विभागों की 319 सेवाएं ऑनलाइन।



सबका साथ-सबका विकास (हरियाणा एक-हरियाणवी एक)

9



10

मुख्य बातें

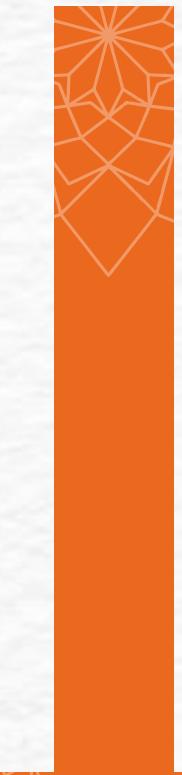
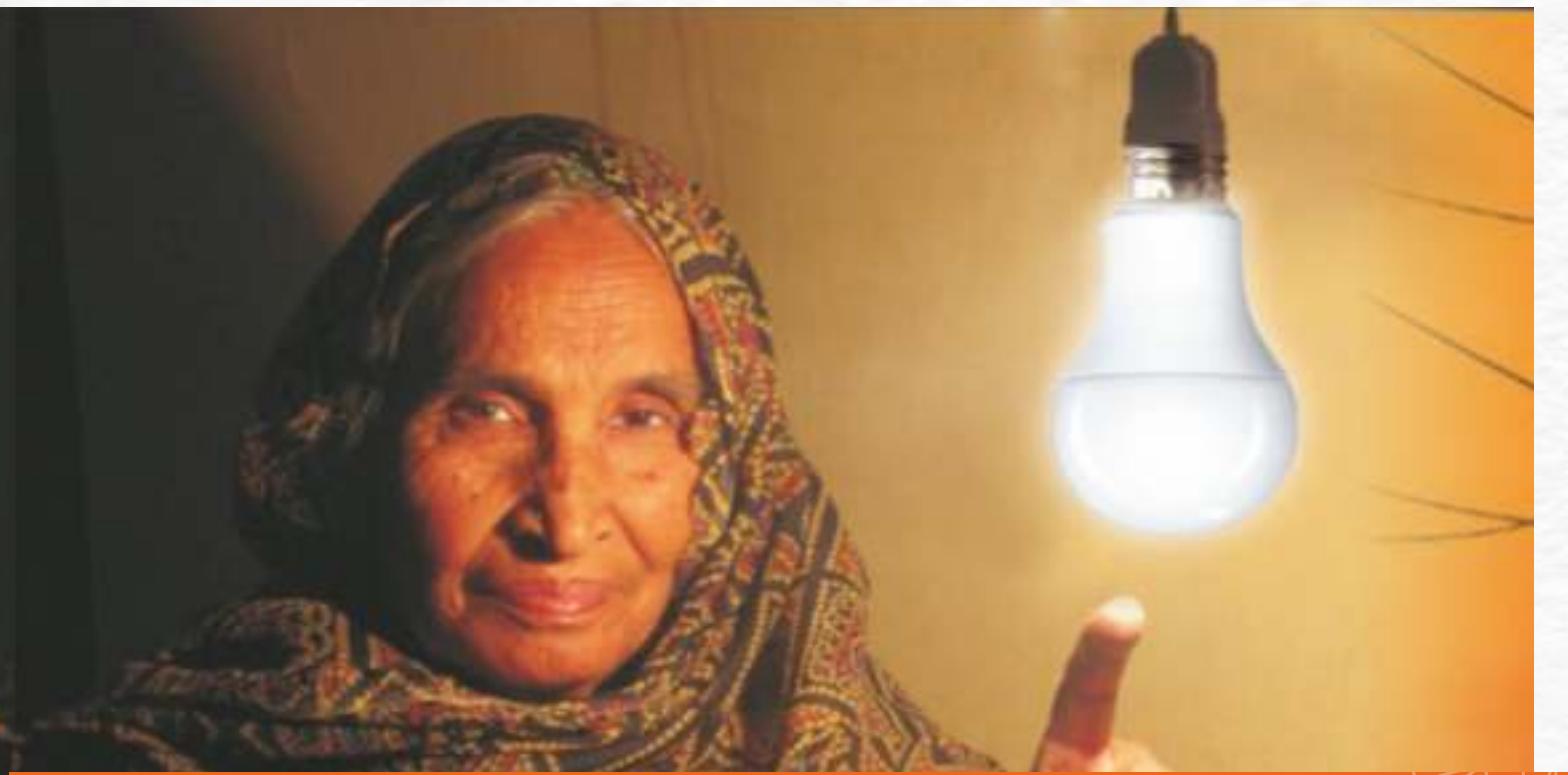
17 नए
राष्ट्रीय राजमार्ग
घोषित, 7 का कार्य पूरा

जल जीवन मिशन
18 लाख घरों
में नल से जल पहुंचाया

म्हारा गांव-जगमग गांव
योजना-5681 गांवों में
24 घण्टे बिजली

हरियाणा में
सभी टेलों पर
पहुंचाया पानी

20 किलोमीटर
के दायरे में
एक कॉलेज



2. हर जिले में मेडिकल कॉलेज व 200 बैड का अस्पताल खोलने का लक्ष्य।
3. 'पदमा स्कीम (वन ब्लॉक—वन प्रोडक्ट)' – 143 ब्लॉकों में क्लस्टर, प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स का विकास शुरू।
4. हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया।
5. दक्षिण हरियाणा के माइनरों में 39 वर्षों बाद पहली बार पहुंचा पानी।
6. अब प्रदेश में किसी भी राशन डिपो से राशन लेने का मिला हक।



सबका साथ-सबका विकास (हरियाणा एक-हरियाणवी एक) बातें नहीं-बदलाव

1. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को आत्मसात करते हुए 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' के मूलमंत्र पर अग्रसर।

फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्तूबर-2014	अब
प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा	10,000 रुपये	15,000 रुपये
प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर मुआवजा	1158 करोड़ रुपये	9414 करोड़ रुपये
बैंकों से किसानों के लेन-देन पर स्टाम्प फीस	2000 रुपये	100 रुपये
गन्ने का भाव प्रति किवंटल	310 रुपये	362 रुपये
प्रति व्यक्ति प्रति दिन दुग्ध उपलब्धता	747 ग्राम	1060 ग्राम
मत्स्य उत्पादन	1 लाख मीट्रिक टन	2 लाख मीट्रिक टन
किसानों को बायोगैस प्लांट लगाने पर अनुदान	8000 रुपये	13,000 रुपये
किसानों को फव्वारा सिंचाई संयन्त्र पर अनुदान	70 प्रतिशत	85 प्रतिशत
मिट्टी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला	43 प्रयोगशाला	98 प्रयोगशाला

कृषि एवं किसान कल्याण



कृषि एवं किसान कल्याण बातें नहीं-बदलाव

- एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य।
- किसानों को फसल भुगतान 72 घण्टे के अंदर। तीन सीजन से फसल खरीद के 56,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में।
- 'मेरी फसल—मेरा ब्यौरा पोर्टल' – 9 लाख किसान पंजीकृत।
- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' – 19.70 लाख किसानों के खातों में 3910 करोड़ रुपये।

- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' – 20 लाख किसानों को 5667 करोड़ रुपये बीमा क्लेम।
- समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण।
- 'एकमुश्त निपटान योजना' – 4.21 लाख किसानों का 1672 करोड़ रुपये का ब्याज व जुर्माना माफ।
- 'सरचार्ज माफी योजना, 2019' – 1,12,300 किसानों के बिजली बिलों की 24 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि माफ।
- 75 से 90 प्रतिशत अनुदान पर 39,448 सोलर पम्प लगाए।
- 'भावांतर भरपाई योजना' – 21 बागवानी फसलों के मूल्य संरक्षित।
- खरीफ सीजन–2021 से बाजरा 'भावांतर भरपाई योजना' में शामिल।
- 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' – बागवानी फसलों का 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक बीमा।
- फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 683 किसान उत्पादक समूहों (FPO) से एक लाख किसानों को जोड़ा।
- बागवानी के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रथापित।
- मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85 प्रतिशत और मधुमक्खी के उपकरणों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान।
- ड्रैगन फ्रूट और खजूर की खेती पर सब्सिडी।
- मशरूम की खेती पर 40 प्रतिशत, वर्टिकल खेती पर 65 प्रतिशत व हाइब्रिड सब्जी पौध पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- हर खेत-स्वरथ खेत अभियान – 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित।
- 'मेरा पानी—मेरी विरासत योजना' – किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता।
- गन्नौर (सोनीपत) में 7000 करोड़ रुपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की Horticulture Market निर्माणाधीन।
- 'पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना' – 1.35 लाख पशुपालक लाभान्वित।
- 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना' – 7.66 लाख पशुओं का बीमा।
- प्रधानमंत्री जी की 'Per Drop-More Crop' अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी।
- 20 साल से अधिक पुराने रजबाहों को दोबारा पक्का करने का काम जारी।

फर्क दिखता है



योजनाएं	अक्टूबर-2014	अब
मेडिकल कॉलेजों की संख्या	8 कॉलेज	13 कॉलेज
मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. सीटों की संख्या	750 सीटें	1735 सीटें
मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. सीटों की संख्या	289 सीटें	653 सीटें
नागरिक अस्पताल	56 अस्पताल	71 अस्पताल
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	470 स्वास्थ्य केंद्र	537 स्वास्थ्य केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	112 स्वास्थ्य केंद्र	122 स्वास्थ्य केंद्र
लिंगानुपात की दर	871	913
मातृ मृत्यु दर	127	91
अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए पी.एस.ए. प्लांट	शून्य पी.एस.ए. प्लांट	94 पी.एस.ए. प्लांट
हरियाणा राज्य का आशा वर्कर्स के मानदेय में योगदान	500 रुपये मासिक	4000 रुपये मासिक



स्वास्थ्य





स्वास्थ्य बातें नहीं-बदलाव

1. सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में 500 दवाइयां और 319 प्रकार के ऑप्रेशन, टेस्ट व दंत चिकित्सा मुफ्त।
2. हरियाणा देश का पहला राज्य, जहां हैपेटाइटिस-सी व बी की दवाइयां मुफ्त।
3. एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा देश में प्रथम।



4. आपातसेवा के लिए 628 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध।
5. घर-द्वार पर मुफ्त चिकित्सा के लिए ई-संजीवनी ओ.पी.डी.।
6. बाढ़सा (झज्जर) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान तथा अम्बाला में अटल कैंसर केयर सेंटर शुरू।
7. 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना' – 29 लाख नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए।
8. देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित।
9. 17 जिलों में पंचकर्मा केन्द्रों पर पंचकर्मा की सुविधा।
10. 347 हेत्थ एंड वैलनैस सेंटर्स खोले गए।





युवा कल्याण



मुख्य बातें

निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग
से 1 लाख युवाओं
को सरकारी नौकरी

भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं
पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप
'सी' व 'डी' की भर्तियों में
साक्षात्कार समाप्त

बार-बार
प्रतियोगी परीक्षा से
छुटकारे के लिए
कॉमन पात्रता परीक्षा

1,59,622 नये
उद्योग लगे,
13 लाख युवाओं
को रोजगार मिला



युवा-कल्याण बातें नहीं-बदलाव

1. उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण।
2. 'सक्षम युवा योजना' – 1.71 लाख युवाओं को 100 घण्टे काम।
3. 'बेरोज़गारी भत्ता योजना' – 3000 रुपये तक मासिक।



4. विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले 15,710 युवाओं को कॉलेज में निःशुल्क पासपोर्ट।
5. ग्रामीण अंचल में रोजगार और बाजार को बढ़ावा देने के लिए 650 हरहित रिटेल स्टोर खोले तथा 300 नये स्टोर खोलने प्रक्रिया पूर्ण।
6. 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' – एक लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।
7. दुधौला (पलवल) में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित।
8. 'सक्षम हरियाणा अभियान' – 92 हजार युवाओं को ओला, उबर, जी4एस, जमैटो और स्वीगी में रोजगार।





शिक्षा

फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्टूबर-2014	अब
राजकीय महाविद्यालय	► 105	► 173
राजकीय महिला महाविद्यालय	► 29	► 60
मिडल स्कूल	► 2397	► 5912
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	► 142	► 186
महिला बस सेवा	► 8 बसें	► 181 बसें
छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा	► 60 कि.मी.	► 150 कि.मी.
राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय	► 13	► 138
ड्रॉप-आउट रेट (प्राथमिक शिक्षा)	► 0.80 प्रतिशत	► शून्य प्रतिशत
कुल दाखिले	► 54.51 लाख	► 57.92 लाख





शिक्षा बातें नहीं-बदलाव

- वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य।
- 1415 कलस्टरों में साइंस, कामर्स, आर्ट्स आदि स्ट्रीम के स्कूल सुनिश्चित किए।
- प्रदेश में एक कि.मी. में प्राथमिक, 3 कि.मी. में माध्यमिक विद्यालय।

- 4081 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले-वे में बदला।
- 500 नये मॉडल क्रेच खोलने का काम जारी।
- 1418 बैग फ्री राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोले।
- सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग हेतु सुपर-100 कार्यक्रम।
- सरकारी स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट।
- ‘चिराग योजना’ – 1956 बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला।
- बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से कक्षा 3 तक Functional Literacy and Numeracy (FLN) कार्यक्रम शुरू।

उच्चतर शिक्षा

- 20 कि.मी. के दायरे में कॉलेज स्थापित।
- KG से PG तक 4 विश्वविद्यालयों में दाखिले।
- पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों की दृश्यानन्द फीस माफ।
- व्यावसायिक व तकनीकी कोर्सों के लिए क्रेडिट गारण्टी स्कीम।
- हिन्दी भाषा में बी.टैक. पाठ्यक्रम 3 विश्वविद्यालयों में शुरू।
- ई-कर्मा – हर साल 3000 उम्मीदवारों को 4–6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण।
- सुनारिया, रोहतक में IIM, कुरुक्षेत्र में NIEIT और उमरी, कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत का पहला NID स्थापित।
- मुख्यमंत्री (सोनीपत) में CIEPT व पंचकूला में NIFT स्थापित।



खेल एवं तंदुरुस्ती



फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्टूबर-2014	अब
ओलम्पिक व पैरालम्पिक पदक विजेताओं को सम्मान राशि	5 करोड़ रुपये	6 करोड़ रुपये
एशियन व पैराएशियन पदक विजेताओं को सम्मान राशि	2 करोड़ रुपये	3 करोड़ रुपये
कॉमनवैल्थ पदक विजेताओं को सम्मान राशि	एक करोड़ रुपये	1.5 करोड़ रुपये
खिलाड़ियों की डाइट मनी	250 रुपये प्रतिदिन	400 रुपये प्रतिदिन
अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता का मानदेय	5000 रुपये मासिक	20,000 रुपये मासिक
तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार विजेता का मानदेय	शून्य	20,000 रुपये मासिक
भीम पुरस्कार विजेता का मानदेय	शून्य	5000 रुपये मासिक
खिलाड़ियों को नौकरी	41	190





खेल एवं तंदुरुस्ती बातें नहीं-बदलाव

- पदक विजेता खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नकद पुरस्कार।
- खिलाड़ियों को 335 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार।
- ओलम्पिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये, एशियन व कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2.5 लाख रुपये एडवांस।
- पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार।

- खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित।
- खिलाड़ियों के लिए क्लास वन से क्लास फोर तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण।
- खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 526 करोड़ रुपये की राशि खर्च।
- चोट के इलाज के लिए पंचकूला में वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित।
- कुरुक्षेत्र, हिसार तथा भिवानी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर।
- हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स गठित।
- राई (सोनीपत) में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित।
- 659 व्यायामशालाएं शुरू और 326 का कार्य प्रगति पर।

खेल पदक तालिका

स्पर्धा	भारत	हरियाणा	
		व्यक्तिगत	सामुहिक
ओलम्पिक खेल—2016	2	1	0
ओलम्पिक खेल—2020	7	3	1
कुल	9	4	1
पैरालम्पिक—खेल 2016	4	1	0
पैरालम्पिक खेल—2020	19	6	0
कुल	23	7	0
एशियन खेल—2014	56	18	2
एशियन खेल—2018	70	15	2
कुल	126	33	4
कॉमनवैल्थ खेल 2014	64	20	0
कॉमानवैल्थ खेल—2018	66	21	0
कुल	130	41	0



सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण

फर्क दिखता है

योजनाएँ

अक्टूबर-2014

अब

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व
विधवाओं को आर्थिक सहायता

3000 रुपये मासिक

10,000 रुपये मासिक

1962, 1965 व 1971 की युद्ध विधवाओं
को आर्थिक सहायता

2000 रुपये मासिक

5000 रुपये मासिक

दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक, टैटराप्लेजिक व
हैमियाल्पेजिक भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता

1500 रुपये मासिक

5000 रुपये मासिक

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने
वाले शहीद सैनिकों के आश्रित

6

360

राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़ रहे
राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति

35,000 रुपये वार्षिक

50,000 रुपये वार्षिक





सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बातें नहीं-बदलाव

1. सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन।
2. युद्ध व आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये।



3. युद्ध व आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान घायल सैनिकों को निशक्तता के आधार पर अनुग्रह राशि 35 लाख रुपये।
4. सैनिक एवं अर्ध सैनिक के आश्रितों के लिए मुफ्त कोचिंग।
5. वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।





सुरक्षा बातें नहीं-बदलाव

1. गुरुग्राम में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर DITAC (Digital Investigation and Technical Analysis Center) स्थापित।



2. मधुबन में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला का ट्रैकिया बार-कोडिंग सिस्टम शुरू।
3. पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट।
4. ऑप्रेशन संवेदना – 4.44 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया।
5. 11,048 जवानों व 2,009 महिला सिपाहियों की पुलिस में भर्ती।
6. गुरुग्राम में महिला आई.आर.बी. बटालियन व हिसार में महिला पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति।
7. पंचकूला में हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित।
8. प्रदेश में 29 साइबर अपराध पुलिस थाने स्थापित।
9. 31 महिला पुलिस थाने स्थापित।



वन एवं पर्यावरण संरक्षण



मुख्य बातें

प्राणवायु देवता पेंशन
योजना – 75 साल से अधिक
आयु के वृक्षों के लिए
2500 रुपये वार्षिक

ऑक्सीवन योजना
पंचकूला व करनाल में
ऑक्सीवन
की स्थापना

विद्यार्थियों को पर्यावरण
के बारे में जागरूक करने
के लिए 5250 ईको
क्लब स्थापित

'कचरे से कंचन' अभियान
के तहत गुरुग्राम में
डीजल ऑटो को स्क्रेप कर
ई-ऑटो चलाए





वन एवं पर्यावरण संरक्षण बातें नहीं-बदलाव

- मुरथल (सोनीपत) में 116 एकड़ तथा यमुनानगर के सढौरा में 11.25 एकड़ जमीन पर नगर वनों का विकास।
- पेड़ों की खेती को ऑक्सीजन की खेती मानते हुए ऑक्सीजन खेती पर 10 हजार प्रति एकड़ वार्षिक प्रोत्साहन।
- प्रदेश में 62 हर्बल पार्क्स विकसित किये।

- ‘जल शक्ति अभियान’ – 68 लाख क्लोनल सफेदा के पौधे लगाये।

जल संरक्षण

- ‘जल बचाओ—कल बचाओ योजना’ – 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के पानी का पावर प्लांट्स व उद्योगों में उपयोग।
- सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना—महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों के 9 एस.टी.पी. से उपचारित जल का सिंचाई के लिए उपयोग।
- Haryana Water Resources Authority, MICADA और Haryana Pond and Waste Water Management Authority का गठन।
- Wetlands के संरक्षण के लिए The State Wetland Authority of Haryana का गठन।
- दो Wet Land, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम व भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, झज्जर को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

वायु प्रदूषण नियंत्रण

- पराली व अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपकरणों पर 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 80 प्रतिशत अनुदान।
- रेड जोन क्षेत्र में स्थित गांवों में पराली न जलाने पर पंचायत को 10 लाख रुपये तक नकद पुरस्कार।
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 29 ‘Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations’ स्थापित।
- मुरथल, सोनीपत में 177 करोड़ रुपये की लागत से कूड़े—कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित।
- एन.सी.आर. जिलों में रेड श्रेणी की सभी औद्योगिक इकाइयों में Online Emission Monitoring Devices स्थापित करना अनिवार्य।



संस्कृति एवं पुरातत्व



मुख्य बातें

पावन सरस्वती नदी को पुनः धरा पर लाने के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन

अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुरुक्षेत्र में भव्य आयोजन और विदेशों (मॉरीशस, लंदन और कनाडा) में भी आयोजन

स्वदेश दर्शन योजना के तहत हरियाणा कृष्ण सर्किट की पहचान





संस्कृति एवं पुरातत्व बातें नहीं-बदलाव

1. फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'हरियाणा फिल्म पॉलिसी' लागू।
2. 'स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन योजना' – 10,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता।



3. 'कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना' – 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता।
4. स्वर्ण जयन्ती गुरु दर्शन यात्रा – 6000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता।
5. राखीगढ़ी, हिसार में 6 एकड़ क्षेत्र में संग्रहालय एवं विवेचन केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी।
6. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम–1857 के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीदी स्मारक।





कर्मचारियों को सुविधाएं



मुख्य बातें

एक्सग्रेशिया पॉलिसी
का लाभ अब अतिथि
अध्यापकों को भी

क्लास वन से
सीधा आई.ए.एस.
बनाने के लिए लिखित
परीक्षा का प्रावधान

नगरपालिका के
सफाईकर्मियों का
10 लाख रुपये
का बीमा

दिव्यांग महिला कर्मचारियों
को चाइल्ड केयर
के लिए 1500 रुपये
प्रति बच्चा विशेष भत्ता

सीवरेज में काम
करते समय व्यक्ति की
मृत्यु होने पर
10 लाख रुपये बीमा



कर्मचारियों को सुविधाएं बातें नहीं-बदलाव

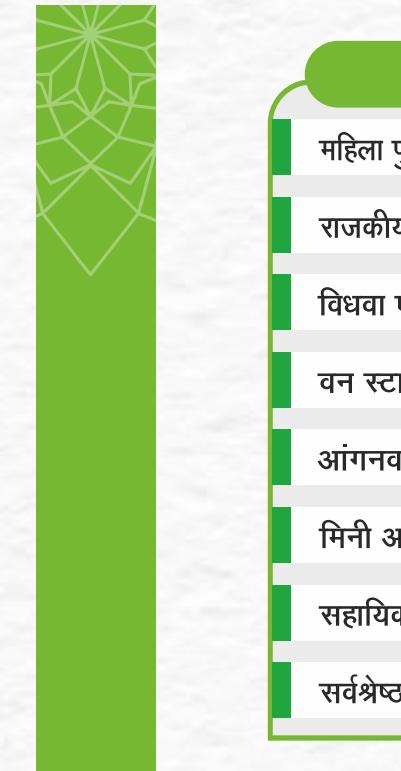
1. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की एच.सी.एस. में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान।
2. 'पारिवारिक पेंशन योजना' – आजीविका से वंचित लड़की को उसकी शादी के बाद तथा पैदा हुए पात्र नि:शक्त बच्चे को पारिवारिक पेंशन का लाभ।

3. सेवा अवधि के दौरान एड्हॉक, अनुबंध व डी.सी. रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिवार को 3 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान।
4. सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में एड्हॉक, कांट्रैक्ट, डेली वेजिज, वर्क चार्ज व आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों को सरकारी भर्तियों में आवेदन के लिए उम्र में छूट।
5. नई एक्सग्रेशिया स्कीम—सरकारी कर्मचारी के 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी।
6. महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केरर लीव के लिए अर्जित अवकाश की शर्तों में छूट।
7. आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा।
8. 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले सफाई कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण।
9. कोरोना वॉरियर की कोविड ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये तथा सरकारी कर्मचारी की कोविड से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का अनुदान।





महिला एवं बाल कल्याण



फर्क दिखता है

योजनाएँ	अक्तूबर-2014	अब
महिला पुलिस थाने	2 थाने	33 थाने
राजकीय महिला कॉलेज	29 कॉलेज	60 कॉलेज
विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन	1000 रुपये मासिक	2500 रुपये मासिक
वन स्टाप सेंटर 'सखी'	0 सेंटर	22 सेंटर
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय	7500 रुपये	12,661 रुपये
मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय	4000 रुपये	11,401 रुपये
सहायिका का मानदेय	3500 रुपये	6781 रुपये
सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार	1000 रुपये	4000 रुपये





महिला एवं बाल कल्याण बातें नहीं-बदलाव

- ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ – 10 लाख बच्चों तथा 3 लाख गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को फोटिफाइड दूध।
- ‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना’ – 23 लाख बी.पी.एल. किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड।

- ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ – 8 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रति महिला 5000 रुपये आर्थिक सहायता।
- पंचकूला, पानीपत, नल्हड़, फरीदाबाद, सोनीपत व पलवल में नए मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित।

महिला सुरक्षा

- ‘बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम–लिंगानुपात सुधरकर 871 से 913 हुआ।
- महिलाओं की सुरक्षा व हर समय उनकी मदद के लिए ‘महिला हेल्पलाइन नम्बर 1091’ शुरू।
- ‘दुर्गा शक्ति ऐप’, ‘दुर्गा शक्ति वाहिनी’, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित।
- सभी बस अड्डों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये।

महिला शिक्षा

- 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित।
- आई.टी.आई. में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपये वजीफा।
- छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।
- 213 मार्गों पर 181 बसें केवल महिलाओं के लिए।
- ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ – अनाथ बच्चों को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता।

सशक्तिकरण

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
- 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को।
- ‘सुकन्या समृद्धि खाता योजना’ – डाकघरों में 6 लाख खाते खोले।

मुख्य बातें

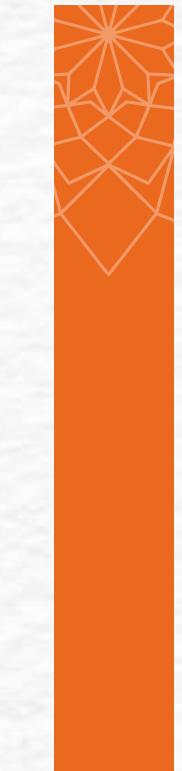
18,422 करोड़ रुपये
के निवेश से 1,59,622
उद्योग (बड़े और एम.एस.एम.ई.)
लगे तथा 12.60 लाख
लोगों को रोजगार

प्रदेश का निर्यात वर्ष
2014 में 69,000 करोड़
रुपये से बढ़कर अब
2.17 लाख करोड़ रुपये हुआ

पदमा स्कीम
(वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट)
143 ब्लॉकों में कलस्टर,
प्रथम चरण में 40 कलस्टर्स
का विकास शुरू

उद्योगों को बढ़ावा
देने के लिए
एम.एस.एम.ई. विभाग
का गठन

व्यापारियों के
लिए ई-रिफंड की
ऑनलाइन सुविधा



उद्योग



उद्योग बातें नहीं-बदलाव

- ‘हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020’ – 5 लाख नए रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपये निवेश तथा 2 लाख करोड़ रुपये निर्यात का लक्ष्य।
- ‘हर अमृत’, कैटल फीड के लिए ‘हर एग्रो’, मिनरल वाटर के लिए ‘हरियाणा फ्रैश’, चीनी के लिए ‘ईक्सू’ ब्राण्ड विकसित किये।



व्यापार

- ‘कॉस्ट ऑफ डुइंग बिजनेस’ को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी।
- ‘स्टैण्डअप इण्डिया योजना’ – 4,794 युवा उद्यमियों को 996 करोड़ रुपये का ऋण।
- ‘उद्योग मित्र योजना’ – उद्योगों की जरूरत अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करना।
- आई.एम.टी. – खरखोदा में 3,300 एकड़ तथा सोहना में 1400 एकड़ भूमि में विकसित।
- गलमार्ट द्वारा पानीपत में वालमार्ट वृद्धि ई-इंस्टीच्यूट शुरू।
- औषध उद्योग के लिए नई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी।
- पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित।
- 20 साल से अधिक समय से काबिज व्यक्तियों का किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत।
- ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ – 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान।
- ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ – 3.15 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान।
- व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल योजना।
- ‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना’ – खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 3000 रुपये की चूनतम मासिक पेंशन।



इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

मुख्य बातें

59 रेलवे ऊपरगामी
पुल/रेलवे भूमिगत पुलों
का निर्माण कार्य पूर्ण तथा
40 का कार्य प्रगति पर

सोनीपत के 'बड़ी'
में 161 एकड़ भूमि पर
रेल कोच रिपेयर फैक्टरी
का निर्माण कार्य पूर्ण

7,717 करोड़ रुपये
से 18,470 कि.मी.
लम्बी सड़कों का सुधार

हिसार
में बना प्रदेश का
पहला एयरपोर्ट

1.25 लाख
नये ट्रांसफार्मर
लगाए

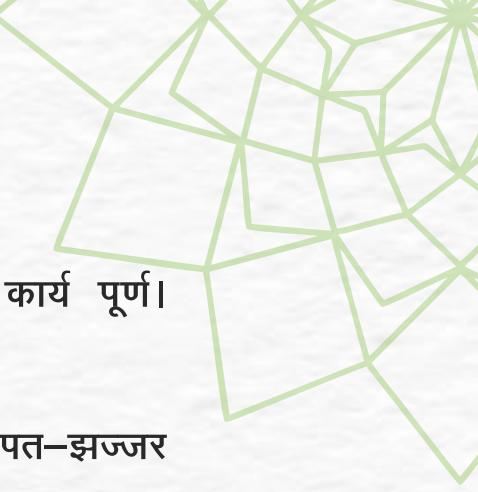




इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बातें नहीं-बदलाव

1. लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए 8700 करोड़ रुपये का मीडियम टर्म एक्सपैंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया।

2. 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित, 7 का कार्य पूरा व 10 पर कार्य जारी।
3. दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुण्डली-मानेसर-पलवल और कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू।
4. लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से सराय कालेखां-करनाल और सराय-कालेखां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच Regional Rapid Transit System Connectivity परियोजना शुरू।
5. पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के लिए 5,618 करोड़ रुपये की लागत से 'हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर'।
6. सोनीपत-जींद रेलवे लाइन पर यातायात शुरू तथा रोहतक-महम-हांसी और करनाल-यमुनानगर रेलवे लाइन का कार्य शुरू।
7. 'रोहतक में एलिवेटिड रेलवे लाइन' का कार्य पूर्ण तथा 'कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे लाइन' का कार्य शुरू।
8. मुंडका-बहादुरगढ़, वाई.एम.सी.ए. चौक फरीदाबाद-बल्लभगढ़, सेक्टर-56, गुरुग्राम-सिकंदरपुर व बदरपुर-मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू।
9. नरेला से कुण्डली, सोनीपत हुडा सिटी सेंटर-रेलवे स्टेशन-सेक्टर-22, साइबर सिटी फरीदाबाद और गुरुग्राम व रेजांगला चौक से सेक्टर-21 द्वारका तक दिल्ली मेट्रो विस्तार को मंजूरी।



10. खेतों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा।
11. नूह क्षेत्र में भू-जल संरक्षण, पेयजल व सिंचाई के लिए कोटला झील के पुनरुद्धार का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
12. 60 नये सब-स्टेशन स्थापित व 544 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि तथा 2000 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई।
13. लाइन लोसिस 30.3 प्रतिशत से घटकर हुआ 16.80 प्रतिशत।
14. 'उजाला योजना' – 1.56 करोड़ LED बल्ब, 2.13 लाख LED द्यूब तथा 60 हजार 709 पंखे वितरित, 411 मैगावाट ऊर्जा की वार्षिक बचत।
15. 255 नहर व 116 नलकूप आधारित जलघर स्थापित, पेयजल बढ़ोतरी के लिए 4,231 नलकूप तथा 990 बूरिंग स्टेशन शुरू, 18 हजार किलोमीटर लम्बी पेयजल पाइप लाइनें बिछाई और 74 मल शोधन संयंत्र स्थापित।
16. 'अमरुत योजना' – 20 शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, पार्क और सीवरेज के लिए 2500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।
17. अंबाला और भिवानी के रिंग रोड और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पिंजौर तथा जींद नगरों के बाइपास बनाए।
18. पानीपत नगर-सफीदों-नगुरां-उचाना-प्रभुवाला-भूना-रतिया-सरदुलगढ़-कालांवाली-मंडी डबवाली को जोड़ने वाला एक नया पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेस-वे का कार्य शुरू।



19. इस्माइलाबाद-नारनौल ट्रांस हरियाणा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य पूर्ण। दिल्ली-वडोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन।
20. पंचकूला-यमुनानगर, अंबाला-कैथल, जींद-नरवाना-पंजाब सीमा तक, सोनीपत-झज्जर राष्ट्रीय राजमार्गों को चारमार्गी बनाया।
21. भिवानी-चरखी दादरी सड़क को चारमार्गी बनाया।
22. 2,397 करोड़ रुपये से 5,466 कि.मी. लम्बी नई सड़कों का निर्माण।





स्वावलंबन - शहरी स्थानीय निकाय

मुख्य बातें

मेयर/अध्यक्ष का सीधे ही चुनाव

पंचायती राज संस्थाओं में मतदाताओं को राइट टू रिकाल का अधिकार

रिहायशी भवनों में चौथी मंजिल का प्रावधान

अंतरराज्यीय परिषद् की तर्ज पर अंतर जिला परिषद् का गठन

686 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया





स्वावलंबन - शहरी स्थानीय निकाय बातें नहीं-बदलाव

1. नगरनिकायों के लाल डोरा में स्वामित्व अधिकार देने की योजना।
2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया।



3. राज्य और केन्द्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायती राज संस्थाओं के खातों में।
4. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत राजस्व।
5. कर संसाधनों से राजस्व का 7 प्रतिशत PRIs को।
6. शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गुरुग्राम, पंचकूला व फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना।
7. गुरुग्राम में 1,003 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही है।
8. करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तथा और भी नई स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी।
9. गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में सिटी बस सेवा शुरू तथा अन्य शहरों में भी शुरू की जाएंगी।



लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी में टाईटल



ग्राम विकास

फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्तूबर-2014	अब
24 घण्टे बिजली आपूर्ति वाले गांव	► 538 गांव	► 5681 गांव
मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन	► 214 रुपये	► 331 रुपये
ग्रामीण चौकीदार का मानदेय	► 3500 रुपये	► 7000 रुपये
चौकीदार की सेवानिवृत्ति आयु	► 60 वर्ष	► 65 वर्ष
ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय	► 8100 रुपये मासिक	► 14,500 रुपये मासिक
गांवों में बिजली बिलों की रिकवरी	► 50 प्रतिशत	► 90 प्रतिशत
नम्बरदारों का मासिक मानेदय	► 1500 रुपये	► 3000 रुपये
ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिक मानेदय	► 2000 रुपये	► 3000 रुपये
ब्लॉक समिति सदस्यों का मासिक मानेदय	► 6000 रुपये	► 7500 रुपये
जिला परिषद् सदस्यों का मासिक मानेदय	► 7500 रुपये	► 10,000 रुपये



ग्राम विकास बातें नहीं-बदलाव

1. गांवों के तीव्र व समग्र विकास के लिए 'हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021' बनाई।
2. 'लाल डोरा मुक्त योजना' के तहत सभी गांव लाल डोरा मुक्त।



3. 10 हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिए 'महाग्राम विकास योजना' लागू।
4. गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए 'हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण' का गठन।
5. 'हर घर नल से जल योजना' – 6803 गांवों में 30.96 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध।
6. 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' – 5681 गांवों को 24 घण्टे बिजली।
7. 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' – 350 गांवों का चयन।
8. 'ग्राम दर्शन पोर्टल' – 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध।
9. आई.टी. युक्त 1876 ग्राम सचिवालय स्थापित।
10. 'शिवधाम नवीकरण योजना' – 73 करोड़ रुपये से 1125 शमशान घाटों का सुधार।
11. '7-स्टार ग्राम पंचायत इन्डर्ड्युश योजना' – प्रदेश के 3930 गांवों को स्टार रेटिंग दी गई।





श्रमिक कल्याण

फर्क दिखता है

योजनाएं	अक्टूबर-2014	अब
अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन	► 5547 रुपये	► 10,243 रुपये
पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी में शागुन राशि	► 51,000 रुपये	► 1.01 लाख रुपये
पंजीकृत श्रमिकों के बेटे की शादी में शागुन राशि	► 11,000 रुपये	► 21,000 रुपये
अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर विधवा आश्रित को सहायता	► 1 लाख रुपये	► 2.5 लाख रुपये
श्रमिकों को दिव्यांग होने पर सहायता राशि	► 30,000 रुपये	► 1.50 लाख रुपये
श्रमिकों को पुरस्कार राशि	► 51,000 रुपये	► 2 लाख रुपये
श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि	► 7000 रुपये	► 10,000 रुपये
श्रमिकों को दाह संस्कार पर सहायता राशि	► 5000 रुपये	► 15,000 रुपये
श्रमिकों के पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों को वर्दी भत्ता	► 2000 रुपये	► 5000 रुपये





श्रमिक कल्याण बातें नहीं-बदलाव

1. श्रम विभाग पोर्टल पर 52.30 लाख श्रमिक पंजीकृत।
2. 'अंत्योदय आहार योजना' – 10 जिलों में श्रमिकों को 10 रुपये में भोजन।
3. काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये।



4. सिलीकोसिस की बीमारी से प्रभावित श्रमिक के पुनर्वास हेतु 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
5. 'मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना'—श्रमिक महिलाओं को 5100 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता।
6. बच्चों की शिक्षा के लिए स्नातक कक्षा तक 20 हजार रुपये वार्षिक तक आर्थिक सहायता।
7. तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के छात्रावास के लिए एक लाख 20 हजार रुपये वार्षिक।
8. श्रमिकों के बच्चों को कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तथा UPSC एवं HPSC की मुख्य परीक्षा की कोचिंग के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
9. श्रमिकों की दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये मासिक और 60 वर्ष की आयु उपरान्त 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि।
10. श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता।





बातें नहीं-बदलाव

1. मातृ भाषा , सत्याग्रहियों व विधवाओं को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन।
2. आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन।
3. आपातकाल के दौरान पीड़ित लोग ताम्रपत्र से सम्मानित।
4. आपातकालीन पीड़ितों को राज्य परिवहन की समान्य बसों में पति-पत्नी दोनों को मुफ्त यात्रा सुविधा तथा वोल्वो बस के किराए में 75 प्रतिशत तक की छूट।
5. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय राजमार्ग—नं. 1, अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीदी स्मारक किया जा रहा स्थापित।

हिंदी आंदोलन
सत्याग्रहियों/आपातकालीन
पीड़ितों को सुविधाएं



